PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Times Of India, Mumbai
Sunday 7th December 2014, Page: 5
Width: 8.41 cms, Height: 16.94 cms, a4, Ref: pmin.2014-12-08.8.7

Two arrested for dumping acid in Ulhasnagar river

V.Narayan@timesgroup.com

Ulhasnagar: The Ambernath police arrested the driver and owner of a tanker late on Friday, for dumping hazardous chemical in the Waldhuni river that left at least 370 residents of Ambarnath and Ulhasnagar with breathing problems on November 29.

A probe revealed that the chemical was transported from southern Maharashtra and dumped in the river. The two accused were produced in a local court on Saturday.

Acting on a tip-off, a team formed by the deputy commissioner of police (zone IV-Thane) Vasant Jadhav, arrested driver Deepak Jaiswal (32) and the vehicle owner Ramesh Gudru (42) on Friday night. "Tests showed the chemical dumped in river is sulphuric acid. More arrests are likely after the arrested accused revealed that the chemical was brought from southern Maharashtra and not Gujarat, which was wrongly reported in some sections of the media," Jadhav told TOI.

The incident came to light in the morning of November 29 when residents of OT Section, Lassi Compound and Samrat Ashok Nagar woke up complaining of headache, stomach ache and dizziness. Many were rushed to nearby hospitals. Residents said they initially did not understand why they felt uneasy but later when they stepped out of their houses they found several others with similar problems. According to the health department, 198 people were treated at Central Hospital, 70 at Shivneri, 74 at Sarvanand, 20 at ECIS Hospital and five people at Trimurti Hospital.

Maharashtra Pollution Control Board officials rushed to the spot and collected water samples. Jadhav said an FIR has been registered with Ambernath police. Police are now investigating which company gave the contract to the accused to dump the hazardous chemicals.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Hindustan Times, Delhi
Monday 8th December 2014, Page: 8
Width: 7.65 cms, Height: 2.73 cms, a4, Ref: pmin.2014-12-08.43.42

PM'S INFORMAL 'RETREAT' PLEASES CMS

Although the Congress CMs opposed scrapping of the plan panel, they praised PM Modi for organising an informal "retreat" where they could chat with him and other CMs. Held at PM's residence, a Congress CM praised Modi for his Swachh Bharat and Make In India campaigns. In return, Modi described the CM as an "able administrator". Modi could be seen sharing laughs even with CMs of opposition-ruled states.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Jansatta, Delhi
Monday 8th December 2014, Page: 10
Width: 16.80 cms, Height: 10.38 cms, a4, Ref: pmin.2014-12-08.33.90

सफाई पर जिलाधिकारी के निर्देश बेअसर

कानपुर, 7 दिसंबर (जनसत्ता)। जनता, व्यापारियों व सफाई कर्मचारियों सहित किसी का साथ नहीं मिलने से स्वच्छ भारत अभियान फिलहाल शहर में दम तोड़ता नजर आ रहा है। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत कुछ ही दिन पहले जिलाधिकारी डॉ. रोशन जैकब ने रामादेवी से आइआइटी तक सफाई अभियान चलाया था और खुद भी इसमें हिस्सेदारी की थी।

जिलाधिकारी ने उस समय निर्देश जारी किया था कि जिन दुकानों के सामने कूड़ा या गंदगी मिलेगी, उनपर जुर्माना किया जाएगा। लेकिन डीएम की बातों का कोई असर नहीं हुआ और दुकानदारों के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। देर शाम बंद होने वाली दुकानों से निकलने वाला कूड़ा दुकानदार सड़कों पर फेंक रहे हैं। बड़ी बाजारों की दुकानों में ज्यादा कचरा निकल रहा है।

कुछ व्यापारियों का कहना है कि दुकान से निकलने वाला कूड़ा कहां फेंका जाए जब आसपास कोई कूड़ेदान ही नहीं है। दुकानदारों ने सफाई कर्मचारियों को दोषी ठहराते हुए कहा कि कूड़ा निकलने के बाद सफाई कर्मचारी इसे समय पर नहीं उठाते हैं जबकि कर्मचारियों का कहना है कि दुकानों से इतना कूड़ा निकलता है कि उसे उठाने के लिए पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। खासकर परचून की दुकानों, कपड़े, जर्दा स्टोरों जैसी दुकानों से बहुत ज्यादा कूड़ा निकलता है। सीसामऊ व शिवाला जैसे बड़े बाजारों में और ज्यादा कूड़ा निकलता है। फिलहाल इन दुकानदारों पर डीएम की जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी का कोई असर नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी तक कोई कार्रवाई तो हुई नहीं। हालात पहले जैसे ही हैं और सड़कों पर गंदगी बढ़ती जा रही है।

दुकानदारों का कहना है कि उनके पास कूड़ा फेंकने की कोई जगह नहीं है। पहले विभिन्न क्षेत्रों में कूड़ा डालने के कंटेनर रखवाए गए थे। उससे भी पहले प्लास्टिक के डिब्बों की व्यवस्था की गई थी लेकिन कुछ ही समय बाद सब बंद हो गया। अगर कोई ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि कूड़ा एक निश्चित स्थान पर ही डाला या जमा किया जाए तो समस्या काफी हद तक कम की जा सकती है। फिलहाल तो सड़क पर ही कूड़ा फेंकने की मजबूरी है। पर यह कूड़ा उठाया नहीं जाता जिससे परेशानी दुकानदारों को ही हो रही है।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Monday 8th December 2014, Page: 7
Width: 14.33 cms, Height: 7.70 cms, a4, Ref: pmin.2014-12-08.32.48

मोदी के बाद शाह की पाठशाला में भाजपा के सीएम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : योजना आयोग के पुनर्गठन के लिए बुलाई गई प्रधानमंत्री की बैठक के बाद भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी के मुख्यमंत्रियों के साथ अलग से बैठक की। भाजपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत हर परिवार में एक बैंक खाता खोलना सुनिश्चित कराने से लेकर पार्टी की सदस्यता अभियान को सफल बनाने के लिए विशेष प्रयास करने को कहा। इस दौरान तीन नए मुख्यमंत्रियों महाराष्ट्र के देवेंद्र फड़नवीस, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर और गोवा के लक्ष्मीकांत पार्सेकर को सम्मानित किया गया।

फड़नवीस और खट्टर विधानसभा में पार्टी की जीत के बाद मुख्यमंत्री बने थे, वहीं पार्सेकर ने मनोहर पार्रिकर के रक्षा मंत्री बनने

- **जन-धन योजना, स्वच्छता अभियान, सुशासन और सदस्यता अभियान पर की चर्चा**
- **हरियाणा, महाराष्ट्र और गोवा के नए मुख्यमंत्रियों को सम्मानित भी किया गया**

के बाद मुख्यमंत्री की शपथ ली थी।

भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार अमित शाह के आवास पर हुई बैठक में प्रधानमंत्री जन-धन योजना, सदस्यता अभियान, सुशासन और स्वच्छता अभियान पर विशेष चर्चा हुई। पार्टी अध्यक्ष ने भाजपा शासित राज्यों में प्रधानमंत्री जन-धन योजना की सौ फीसद सफलता सुनिश्चित करने को कहा। उनका कहना था कि इन राज्यों में हर परिवार में कम-से-कम एक खाता होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने के लिए मुख्यमंत्रियों को अपने-अपने राज्यों में विशेष ध्यान देना चाहिए। विशेष सदस्यता अभियान के तहत भाजपा ने अगले साल 31 मार्च तक 10 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी पीपुल्स पार्टी आफ चाइना है, जिसके आठ करोड़ सदस्य हैं। अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों को 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में पूरी तैयारी के साथ मनाने के लिए कहा।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Dainik Jagran, Delhi
Monday 8th December 2014, Page: 15
Width: 20.18 cms, Height: 16.08 cms, a4r, Ref: pmin.2014-12-08.32.130

बेकार पानी को शोधित कर बढ़ाई जलापूर्ति

सप्ताह का साक्षात्कार

दिल्ली में पानी की आपूर्ति व मांग में भारी अंतर है। पेयजल किल्लत दूर करने के लिए मूनक नहर से दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिलना है। अब बरसाती पानी के भंडारण के लिए यमुना में तीन बैराज बनाने की बात भी हो रही है। दिल्ली में पानी किल्लत, मूनक नहर विवाद व जल बोर्ड की तैयारियों के मद्देनजर जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) विजय कुमार से जागरण संवाददाता रणविजय सिंह ने बातचीत की। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश।

■ दिल्ली में पेयजल आपूर्ति व मांग की मौजूदा स्थिति क्या है?

-मौजूदा समय में हर रोज दिल्ली में 1080 एमजीडी पानी की जरूरत है। जबकि 835 से 840 एमजीडी पानी की आपूर्ति होती है। इसमें 603 एमजीडी पानी अलग अलग नदियों से मिलता है। इसमें से 50 फीसद पानी यमुना, 35 फीसद गंगनहर व 15 फीसद रावी व व्यास नदी से मिलता है। इसके अलावा भूजल से 80 एमजीडी व बेकार पानी को शोधित कर 142 एमजीडी पानी की आपूर्ति हो रही है। निश्चित रूप से पानी की मांग व आपूर्ति में अंतर है। जिस रफ्तार से दिल्ली की जनसंख्या बढ़ रही है उससे अनुमान है कि 2021 में प्रतिदिन 1380 एमजीडी पानी की जरूरत होगी।

■ पानी की मांग व आपूर्ति में भारी अंतर को बोर्ड कैसे दूर करेगा?

-जल बोर्ड को जो कच्चा पानी मिलता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है। इसलिए जल बोर्ड की कोशिश है कि मौजूद पानी बर्बाद नहीं हो। दुनिया भर के जलशोधन संयंत्रों में शोधन के दौरान आठ फीसद पानी बेकार चला जाता है। लेकिन जल बोर्ड ने अपने शोधन संयंत्रों में बेकार पानी को दोबारा शोधित करने के लिए उपकरण लगाए हैं। इससे मौजूदा समय में बेकार पानी को शोधित कर आपूर्ति बढ़ाई गई है और इस तरह 142 एमजीडी पानी की आपूर्ति की जा रही है। इससे मांग व आपूर्ति में अंतर कुछ कम हुआ है। बोर्ड अन्य सरकारी व प्राइवेट महकमों को भी बेकार पानी को शोधित कर दोबारा पीना छोड़कर अन्य कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके अलावा मूनक नहर से दिल्ली को 95 एमजीडी पानी मिलना है। इसके अलावा बरसाती पानी के भंडारण के लिए यमुना में तीन डैम बनाए जाएंगे। इससे पानी आपूर्ति बढ़ेगी।

■ मूनक नहर के मामले में हरियाणा व दिल्ली के बीच लंबे समय से विवाद है। ऐसे में जल बोर्ड को अतिरिक्त पानी मिलने की कितनी उम्मीद है?

-इस मामले को हल करने के लिए हरियाणा सरकार से कई स्तरों पर बातचीत हो रही है। बातचीत सकारात्मक भी है। पक्की मूनक नहर बनाने के लिए जल बोर्ड ने करीब 500 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसलिए नाउम्मीद होने का कोई मतलब ही नहीं बनता।

■ विवाद का असल कारण क्या है। पक्की नहर बनने के बाद कोई अध्ययन हुआ, जिससे यह पता चल सके कि कितना पानी बच रहा है?

-पक्की नहर बनने की योजना इस आधार पर ही तैयार की गई थी कि कच्ची नहर से पानी आपूर्ति के कारण 30 फीसद पानी बर्बाद हो जाता है। पक्की नहर बनने से वह बर्बादी रुकेगी।

■ पहले पक्की मूनक नहर से 80 एमजीडी अतिरिक्त पानी की बात हुई थी अब जल बोर्ड अधिक दावा क्यों कर रहा है?

-मूनक नहर की योजना बनने के बाद दिल्ली में नांगलोई जल संयंत्र के लिए रावी और व्यास नदी से अतिरिक्त पानी उपलब्ध कराने का समझौता हुआ था। मूनक नहर से जो पानी मिलना है, उसमें से 37 एमजीडी यमुना का और 58 एमजीडी पानी रावी और व्यास का है, जो दिल्ली के हिस्से का है। इस तरह मूनक नहर से 95 एमजीडी अतिरिक्त पानी मिलना है।

■ रेणुका बांध से भी दिल्ली जल बोर्ड को पानी मिलना है, उस परियोजना क्या हुआ?

-दिल्ली जल बोर्ड को रेणुका बांध, लखवर व्यासी व किशाऊ बांध से पानी मिलना है। इन परियोजनाओं के लिए जल बोर्ड 200 करोड़ की भुगतान हो चुका है। ये तीनों राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित हो चुकी हैं। केंद्र सरकार ने रेणुका बांध परियोजना के लिए बजट में राशि तय की हैं।

■ पाइपलाइनों में रिसाव से पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जल बोर्ड क्या कर रहा है?

-पानी के रिसाव का पता लगाने के लिए मुख्य पाइपलाइनों में फ्लो मीटर लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा उपभोक्ता के स्तर पर होने वाली बर्बादी को रोकने के लिए कनेक्शन की लाइनों को बदलने की योजना तैयार की जा रही है।

■ सीवर विकास शुल्क घटाने की घोषणा दो बार की गई पर हकीकत में ऐसा नहीं हुआ, इसका क्या कारण है?

-यह सच है कि सीवर शुल्क घटाने की योजना है लेकिन अधिसूचना जारी होना शेष है, फिलहाल यह विचाराधीन है। इस पर सरकार फैसला लेगी।

■ जापान की एजेंसी जेआइसीए ने 2017 तक यमुना को साफ करने का दावा किया है, क्या यह संभव है?

-जापानी एजेंसी की अध्ययन रिपोर्ट जल बोर्ड के पास नहीं है, इसलिए एजेंसी ने क्या दावा किया, यह मुझे नहीं मालूम।

■ इंटरसेप्टर सीवर लाइन पैकेज-1 से कितनी मात्रा में सीवरेज शोधन हो रहा है?

-यमुना में सीवर का गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए जल बोर्ड 59 किलोमीटर लंबा इंटरसेप्टर सीवर लाइन विकसित कर रहा है। हाल ही में जिस द्वारका पप्पनकलां इंटरसेप्टर सीवर लाइन की शुरुआत की गई है, वह पैकेज-1 का हिस्सा भर है। इसमें अभी कुछ और काम होने हैं। वैसे द्वारका पप्पनकलां इंटरसेप्टर सीवर लाइन से पालम नाले के गंदे पानी को सीवरेज शोधन संयंत्र में ले जाकर शोधित किया जा रहा है और वह बेहतर काम कर रहा है।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Mail Today, Delhi
Monday 8th December 2014, Page: 3
Width: 19.30 cms, Height: 23.62 cms, a3, Ref: pmin.2014-12-08.29.11

Landfill sites pose big threat to Delhi

By **Baishali Adak** in New Delhi

A HUGE environmental hazard looms over the Capital as the city's three landfill sites — Okhla, Bhalswa and Ghazipur — continue to accumulate garbage beyond their shelf life.

A study done by Jawaharlal Nehru University's Department of Environment shows that the groundsoil of these three sites harbour organic pollutants exceeding the permissible limits by up to 158 times.

These sites were found to be high on compounds like aliphatics, terpenoids, benzenes, ketones, pharmaceuticals and phthalates which do not degrade with time, enter the food chain quickly and cause a variety of health issues such as hormone disruption, reproductive disorders, learning disabilities, heart diseases, diabetes and cancer.

Additionally, Ghazipur was found to accumulate compounds which are more cytotoxic, that is human cell killing, in nature. On the other hand, Okhla contained more of genotoxic compounds which cause alteration in cell DNA.

The researchers fear that the contaminated liquid emanating from the garbage, called leachate, will pollute the groundwater beyond cure. This can prove to be disastrous for large populations residing near these three landfill sites which use groundwater. It will also further pollute Yamuna which runs along the course of these three sites.

Pooja Ghosh, a research scholar and co-author of the study, said, "The national Capital produces more than 9,000 tonnes of Municipal Solid Waste daily. The Ghazipur, Okhla and Bhalswa sites are all unengineered, that is lacking a baseline, and oversaturated with waste. Based on amount of rainfall, age of the landfill as well as waste composition and degradation stage of waste, the sites continuously leak contaminants in the groundwater."

"Samples of leachate were collected at the three landfill sites — Ghazipur, Okhla and Bhalswa — in the summer of May 2012. Several chemicals were found in leachate that may act in a synergistic and additive manner to cause toxic effects on organisms such as aquatic species in Yamuna and the human population living alongside the sites."

Toxic compounds, which affect human cells, were found at the Ghazipur site.

> "Based on rainfall, age of landfill and waste composition, the sites continuously leak contaminants in the groundwater."
> —Pooja Ghosh, research scholar

All the samples were characterised by dark colour, unpleasant odor, alkaline pH, high conductivity and relatively high concentrations of organic matter. Unfortunately, no standard maximum allowable discharge limit for landfill leachate is there in India, so the limits set by developed countries such as Germany were used as a guideline in the present study. Leachate samples were found to exceed the permissible limits of leachate discharge for iron and chromium. High concentrations of cadmium and copper were also found at Okhla and Ghazipur respectively.

> Researchers fear that the contaminated liquid emanating from the garbage, called leachate, will pollute the groundwater

Co-author and JNU environment department dean Indu Shekhar Thakur and Asmita Gupta said, "The three sites must be closed immediately and further sites engineered and lined appropriately."

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Monday 8th December 2014, Page: 6
Width: 3.94 cms, Height: 15.11 cms, a4, Ref: pmin.2014-12-08.25.69

पहले बनवाओ शौचालय, उसके बाद लेंगे फेरे

जयपुर (नेशनल ब्यूरो)। देशभर में चल रहे स्वच्छता अभियान और खुले में शौच मुक्त भारत जैसे अभियानों का असर नई पीढ़ी पर दिखने लगा है। राजस्थान के धौलपुर जिले में एक युवती ने इस मामले में एक मिसाल पेश की है। युवती का जहां रिश्ता तय हुआ, उस घर में शौचालय नहीं था। उसने ससुरालवालों से पहले शौचालय बनवाने का आग्रह किया। शौचालय बनने के बाद ही अब शादी की तिथि तय हो सकी है।

आठ फरवरी को शादी

वाकया गांव पिपहेरा का है। यहां के बंटू पराशर का रिश्ता बाड़ी की युवती पूनम से तय हुआ। फिर शादी की तिथि निश्चित करने की चर्चा दोनों पक्षों के बीच चलने लगी। इस बीच युवती को ससुराल में शौचालय नहीं होने की जानकारी मिली। उसने अपने ससुराल वालों से शादी की तिथि तय करने से पहले घर में शौचालय बनवाने का आग्रह किया। भावी बहू के आग्रह पर उन्होंने शौचालय बनवा दिया। अब विवाह की तिथि आठ फरवरी तय हो गई है। अब दोनों घरों के लोग शादी की तैयारी में जोर-शोर से जुट गए हैं।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Monday 8th December 2014, Page: 7
Width: 32.50 cms, Height: 9.25 cms, a3r, Ref: pmin.2014-12-08.25.70

ट्रेनों में चादर व तकिया कवर अब होंगे 'यूज एंड थ्रो'

हबीबगंज-निजामुद्दीन समेत जोन की कुछ ट्रेनों में शुरू होगा ट्रायल

शशिकांत तिवारी >> भोपाल (मप्र)

ट्रेनों के एसी क्लास में यात्रा के वक्त अब आपको तकिया कवर, चादर और तौलिया में बदबू की शिकायत नहीं मिलेगी। यात्रियों की शिकायत दूर करने के लिए रेलवे नया प्रयोग करने जा रहा है। उन्हें अब डिस्पोजेबल चादर, तकिया और तौलिया (लिनेन) मिलेगा। इन्हें एक बार उपयोग कर फेंक दिया जाएगा। फिलहाल इसकी शुरुआत तकिया कवर से होगी। पश्चिम मध्य रेल की कुछ चुनिंदा ट्रेनों में इसका ट्रायल शुरू होने जा रहा है। इसमें हबीबगंज-निजामुद्दीन भोपाल एक्सप्रेस भी शामिल है।

रेलवे बोर्ड के निर्देशं पर जोन मुख्यालय ने इसकी तैयारी शुरू दी है। जोन के एक अधिकारी ने बताया कि डिस्पोजेबल लिनेन बनाने वाली कंपनियों को इंडेंट (सप्लाई ऑर्डर) दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि यात्री अभी कॉटन से बना लिनेन उपयोग कर रहे हैं। वे डिस्पोजेबल कपड़ा उपयोग करने के आदी नहीं हैं। ऐसे में चादर, तकिया और तौलिया एक साथ बदलने से उन्हें असहज लग सकता है। पहले तकिया कवर दिया जाएगा। यात्रियों से फीडबैक लेने के बाद बेडशीट और तौलिया भी डिस्पोजेबल दिया जाने लगेगा। कंबल अभी पुराने तरीके के ही इस्तेमाल होंगे।

यह होगा फायदा

- दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
- कॉटन के मुकाबले लिनेन ज्यादा हाईजैनिक होगा।
- इसे रिसाइकिल कर दोबारा उपयोग किया जा सकेगा।
- री-पैकिंग का अंदेशा नहीं रहेगा।
- यात्रियों को दाग-धब्बे और पुराने कपड़ों से निजात मिल जाएगी।
- लिनेन की चोरी कम हो जाएगी।

यह है खासियत

>> गर्मी रोकने वाला
>> बैक्टीरिया रोधी
>> फिल्टर >>लचीलापन
>> आसानी से मुड़ने लायक
>> गद्दीदार
>> आवाज कम आती है
>> सोखने की क्षमता
>> खिंचाव।

इतना महंगा पड़ सकता है

चादर :	60 रुपए प्रति नग तक
तौलिया :	20 से 30 रु. प्रति नग
तकिया कवर :	6 से15 रु. प्रति नग

उपयोग करने के बाद लौटाना बेचेगा रेलवे

डिस्पोजेबल लिनेन के ज्यादा उपयोग के बाद भी इसके निबटान (डिस्पोजल) में कोई समस्या नहीं आएगी। इसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है। सप्लायर ने खुद करीब 40 रुपए किलो के हिसाब से पुराने लिनेन खरीदने की बात कही है।

यहां पहले से हो रहा इस्तेमाल

>> पैलेस ऑन व्हील और कुछ अन्य पर्यटक ट्रेनों में डिस्पोजेबल लिनेन यात्रियों को दिया जा रहा है।
>> भोपाल एक्सप्रेस में एसी 1 में डिस्पोजेबल तकिया कवर करीब 5 साल से दिया जा रहा था। 8 माह से उसकी जगह कॉटन का कवर दिया जाने लगा है।

"कुछ ट्रेनों में प्रयोग के तौर पर हम डिस्पोजेबल लिनेन देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तकिया कवर दिया जाएगा। यात्रियों से अच्छा फीडबैक मिला तो बेडशीट और तौलिया भी डिस्पोजेबल शुरू कर दिया जाएगा।

- आलोक दवे, सीएमई, पश्चिम मध्य रेल

"हमने कुछ सप्लायरों से इस संबंध में पूछा है। बेड शीट करीब 150 रुपए में पड़ रही है। तौलिया 30 और तकिया कवर 6 रुपए में पड़ रहा है। इस पर अमल जोन स्तर से किया जाना है।

- राजीव चौधरी, मंडल रेल प्रबंधक

इस तरह बनता है डिस्पोजेबल लिनेन

इसे बनाने के लिए पॉलीमर का उपयोग किया जाता है। पॉलीमर रासायनिक तत्वों से बने मालीक्यूल होते हैं। पहले इनसे रेशे बनाए जाते हैं। तेल से बनी हुई कुछ चीजों और पुराने पालीएस्टर से नया कपड़ा तैयार किया जाता है।

एक्सपर्ट की राय...

नुकसानदेह है पॉलीमर

डिस्पोजेबल लिनेन नॉन वोवेन फेब्रिक से बनाए जाते हैं। इसमें कपड़े की बुनाई नहीं की जाती है। इसे बनाने में पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, जो रासायनिक तत्वों से बनता है। यह हाइजेनिक होता है, लेकिन इसके ज्यादा इस्तेमाल से स्किन डिसीज होने का खतरा रहता है।

- डॉ. अनुराग पयासी,
साइंटिस्ट, दवा निर्माता कंपनी

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Monday 8th December 2014, Page: 8
Width: 7.70 cms, Height: 19.01 cms, a4, Ref: pmin.2014-12-08.25.78

आदर्श ग्राम की बाधाएं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदलने के लिए 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के साथ एक विशेष पहल की। यह योजना कामयाब रही, तो निश्चित ही इससे भारत में ग्राम विकास का नया मॉडल सामने आएगा। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने की राह में कई रुकावटें हैं। इस तरफ ध्यान खुद कई सांसदों ने खींचा है। ऐसे में सवाल है कि सामाजिक समावेशन के लिए प्रधानमंत्री की पहल पर शुरू हुई तीनों योजनाओं (बाकी दो अन्य योजनाएं 'भारत स्वच्छता अभियान' और 'जन धन योजना' हैं) से जो सकारात्मक माहौल बना है, क्या उसे तार्किक मुकाम तक पहुंचाया जा सकेगा? 'सांसद आदर्श ग्राम योजना' के साथ सबसे बड़ा मुद्दा यह सामने आया है कि इसके लिए अलग से धन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। बल्कि सांसदों से अपेक्षा की गई है कि वे अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड (एमपीलैड) का उपयोग करें। साथ ही इंदिरा आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना जैसे ग्रामीण विकास से जुड़े कार्यक्रमों तथा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कोष को समन्वित करें, जिससे चुने गए गांव को विकास के लिहाज से आदर्श बनाया जा सके। उस गांव के ऐसे समग्र विकास के लिए और भी ज्यादा धन की आवश्यकता हो, तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) के तहत कंपनियों ने सामाजिक विकास के लिए जो धन रखा है, उसे जुटाने की कोशिश करना चाहिए। वे चाहें तो परोपकारी संस्थाओं की मदद भी ले सकते हैं। जाहिर है, ऐसा करना आसान नहीं है। जहां तक एमपीलैड का संबंध है, तो उस पर दूसरे मंत्रालयों की भी निगाहें हैं। मसलन, पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने सांसदों से इस धन से घरों और सार्वजनिक स्थलों पर शौचालय एवं कचरा प्रबंधन की परियोजनाएं बनाने को कहा है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाने के लिए इस धन का उपयोग करने का अनुरोध किया है। इसके लिए बाकायदा सांसदों को पत्र भेजे गए हैं। इसके अलावा एक चुनौती सियासी है। सांसद आशंकित हैं कि अपनी कोशिशों से वे एक गांव को आदर्श बना देंगे, तो उससे उनके चुनाव क्षेत्र के दूसरे सैकड़ों गांवों में ईर्ष्या का भाव पैदा होगा, जिसकी कीमत उन्हें चुनाव के वक्त चुकानी पड़ सकती है। फिर गांवों के चयन की कसौटी का भी प्रश्न है। भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने जब एक गांव का चयन किया, तो आलोचना हुई कि कानपुर से सिर्फ तकरीबन 15 किलोमीटर दूर स्थित ऊंची इमारतों वाले और तेजी से शहर का रूप लेते गांव का वे और क्या विकास करेंगे? बहरहाल, ये मुद्दे भी अहम हैं, परंतु धन की उपलब्धता से जुड़ा मसला निर्णायक महत्व का है। प्रधानमंत्री से अपेक्षा है कि वे इस पर ध्यान देंगे। व्यावहारिक दिक्कतें दूर ना हुईं तो उनकी इस प्रिय योजना की सफलता संदिग्ध हो जाएगी। अत: आशा है, वे शीघ्र हस्तक्षेप कर ग्रामीण विकास के अपने सपने को साकार करने का रास्ता सुगम बनाएंगे।

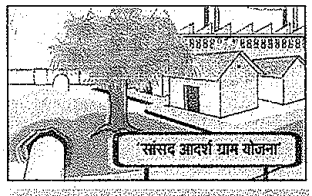

'सांसद आदर्श ग्राम योजना' सफल रही तो निश्चित ही देश में ग्राम विकास का नया मॉडल सामने आएगा। लेकिन इसकी राह में कई रुकावटें हैं।

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Deccan Chronicle, Hyderabad
Sunday 7th December 2014, Page: 6
Width: 28.02 cms, Height: 34.97 cms, a3, Ref: pmin.2014-12-08.13.9

Private firm responsible for solid waste management operations served notice by TS pollution body

Dump trashed for stink

SUDHEER GOUTHAM | DC
HYDERABAD, DEC. 6

Ramky, the firm that runs the solid waste management project at the Jawaharnagar garbage dump yard on the city outskirts, has been served a notice by the Telangana State Pollution Control Board for multiple violations of environmental laws and causing health hazards, when the TSPCB examined the dumping site.

The foul smell emanating from the dumping yard has been taking a toll on the health of over 1 lakh residents of the nearby colonies. The stench is distinctly noticeable even in the residential areas about 7-8 km from the dumping yard.

Anil Kumar, a member secretary of the TSPCB, said, "Ramky has been served notice on the foul smell issue. Even the slaughterhouse that is being operated without any scientific disposal system has been served notices. They have been given two days to respond in detail."

The environmental engineers of TSPCB, who examined the site, found that over 30 tonnes of waste produced every day from a slaughterhouse was being openly dumped in the yard without treatment. The garbage dump mixed with slaughter house waste, was found on the open without any mandatory capping.

The Greater Hyderabad Municipal Corporation was found collecting ₹10 crore lease fee from the slaughterhouse unit ignoring the mandatory disposal system.

Even the Ramky Company, which maintains the treatment plant, does not have operational leachate (the liquid oozing from the dump) treatment plant.

Environmental engineers of TSPCB questioning the Ramky representative. "The leachate treatment plant was not operational during our visit. Even the plant is too small to treat hundreds of tonnes of garbage produced in the city." The oozing leachate has been corroding stones which it comes in contact with.

TSPCB officials also found fault with GHMC for leasing out the slaughter house to a contractor without arranging a system of disposal of the animal waste. "Ramky has been entrusted with the scientific disposal of the solid waste garbage, but not the animal waste from the slaughterhouse unit, which is a commercial affair of an individual," said an official of TSPCB.

Ramky claimed that it got the contract for Solid Waste management in 2009 and the existing dump (uncapped) already existed then, which will be taken care of in the coming days.

Pulled up by AUTHORITIES

RAMKY, THE FIRM THAT RUNS THE SOLID WASTE MANAGEMENT PROJECT AT JAWAHARNAGAR GARBAGE DUMP YARD ON THE CITY OUTSKIRT, HAS BEEN SERVED A NOTICE BY THE TELANGANA STATE POLLUTION CONTROL BOARD

The environmental engineers of TSPCB, who examined the site, found that over 30 tonnes of waste produced every day from a slaughter house was being openly dumped in the yard without treatment.

The stench is distinctly noticeable even in the residential areas about 7-8 kilometres from the dumping yard.

Ramky has capped only around 30 per cent of the dumping yard and is yet to cover 70 per cent, which is said to be the key reason for this.

The city generates 3,500 metric tonnes of garbage every day, and all of it is dumped at Jawaharnagar. The GHMC has three temporary dumping yards at Kavadiguda, Yosufguda and Necklace road and one permanent dump ground. The TRS government has directed the Corporation to identify sites to set up five more dump yards

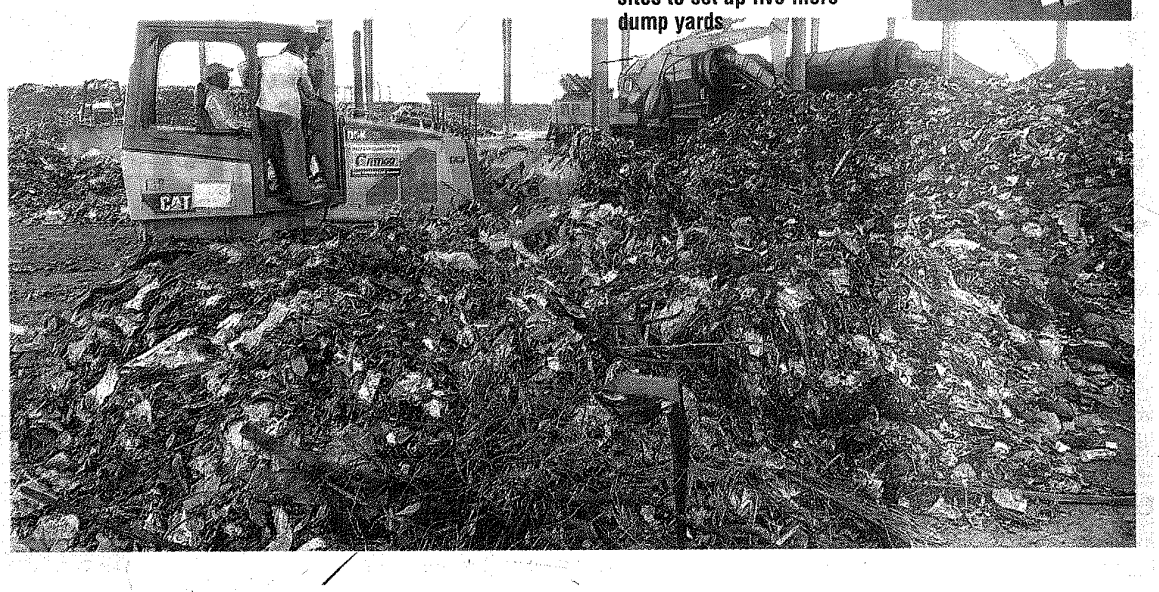

Ramky has been served notice on the foul smell issue. Even the slaughter house that is being operated without any scientific disposal system has been served notices.

— ANIL KUMAR
Member Secretary, TSPCB

The garbage is mixed up, including animal waste. Unless the garbage is segregated and dumped, it cannot be treated scientifically and odour cannot be prevented from emanating

— M. VENKATESH
Jawaharnagar, project head

Yes, we did receive complaints of bad odour from residents. However, the problem no longer exists as our teams checked the industries that were releasing the gases without proper filtration

— P. VEERANNA
Scientific officer, TSPCB

Twice or thrice in a week children at home have breathing issues. I am worried about the long term effects of the odour on them.

— M. LALITA
IT PROFESSIONAL

Methane from dump causes frequent flames

CORRENA SUARES | DC
HYDERABAD, DEC. 6

Untreated animal waste is piling up on the hillock at GHMC's permanent dumping yard at Jawaharnagar, emanating a foul smell that is intolerable. More dangerously, methane from the dumping yard is diffused into the atmosphere, leading to frequent flames and smoke. The situation is worse during the rainy and winter seasons due to moisture in the air.

Ramky has failed to set up proper apparatus to keep the dumping yard dry and the Pollution Control Board has had to step in and take action against the company and GHMC officials for endangering the lives of lakhs of people residing in the colonies in the vicinity.

Ramky has capped only around 30 per cent of the dumping yard and is yet to cover 70 per cent, which is said to be the key reason for this. Venkatesh, the project head at Jawaharnagar, blames the GHMC, which is involved in collecting the garbage.

"Though we (Ramky) are involved in the scientific disposal of the garbage, the collection is done by GHMC. The garbage is mixed up, including animal waste. Unless the garbage is segregated, it cannot be treated scientifically and the stench cannot be prevented."

Asked about capping the garbage, he adds, "Yes, the odour to an extent can be reduced by capping the dump. We are working on it."

Just two days ago the executive engineer and his team visited the site; there is no deliberate burning of garbage but auto ignition is common in any dumping yard.

— N. RAVI KIRAN
Additional commisioner, Health & Sanitation

For several years, the stink from the Jawaharnagar dumping yard had been restricted to only the colonies surrounding it, namely Jawaharnagar, Dammaiguda, Shantinagar, Sivajinagar and Ambedkarnagar. However, now colonies like Saket, Arul Colony, Arun Nagar, Bank Colony, A.S. Raonagar Road, DLR Enclave, Madhavapuri, Bhaskarraonagar, Lake View Colony, Manik Sai, Kalyan Gardens and parts of Sainikpuri and Defence Colony are also effected. The smell is particularly foul in the early mornings and evenings.

People are suffering vomiting, nausea, headache and respiratory diseases, complaint residents.

N. Ravi Kiran, additional commissioner for health and sanitation, said, "Just two days ago the executive engineer and his team visited the site; there is no deliberate burning of garbage but auto ignition is common in any dumping yard. The smell may be because of auto ignition. GHMC will instruct the executive engineer to visit the site again."

The leachate oozing from the old dump site.

PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

MINT, Delhi
Monday 8th December 2014, Page: 31
Width: 29.32 cms, Height: 26.42 cms, a3r, Ref: pmin.2014-12-08.48.107

theirview

Making water conservation pay

Protecting water at its source can be cheaper and more efficient than treating it after it has been polluted

Giulio Boccaletti
is the global managing director for water at The Nature Conservancy.

RAMESH PATHANIA/MINT

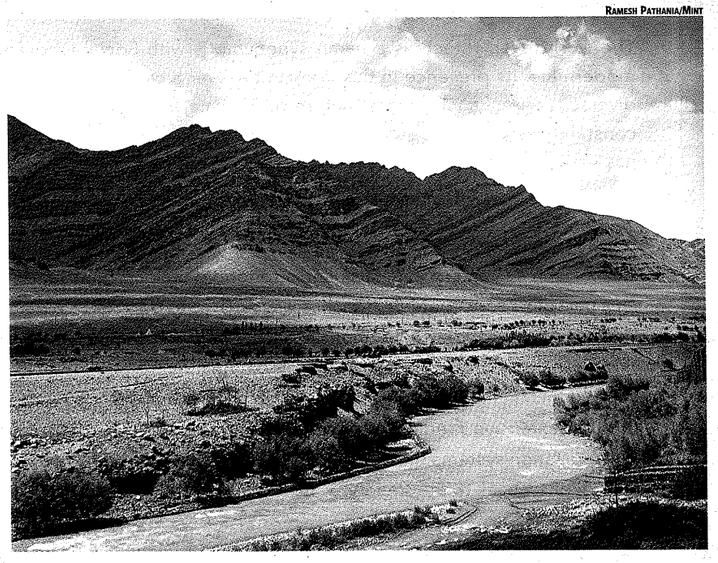

Call it a sign of the times. Rarely a month passes in which a water crisis does not make headlines somewhere in the world. In early August, an algal bloom in Lake Erie, the result of agricultural runoff, contaminated drinking water in Toledo, Ohio. In September, the reservoirs in China's Henan province dried up, leaving crops to shrivel and forcing some residents to drink from puddles on the ground. In late October, the city of Hyderabad, India, discovered that its water supply might be diverted next year for agricultural uses upstream, leaving some eight million people to wonder where they will find the 190 million gallons of water they need every day.

City officials usually respond to such supply crises by upgrading their water infrastructure, namely, drilling, damming, and laying pipes. Every day, the world's largest 100 cities move 3.2 million cubic meters of water more than 5,700km to address local water shortages or problems with pollution. But this is an expensive solution, one that only the wealthiest cities can afford. It also puts city managers at odds with environmentalists, who campaign for restrictions on development to ease pressure on forests and watersheds. Fortunately, it is not the only option.

Nature, it turns out, can play an important—and so far largely untapped—role in water delivery and treatment. Protecting water at its source can be cheaper and more efficient than treating it after it has already been polluted. In a new report, my colleagues at The Nature Conservancy, the C40 Climate Leadership Group, and the International Water Association show that investing in forest protection, reforestation, stream bank restoration, improved agricultural practices, and forest-fire management can reduce the amount of pollutants flowing into supplies of drinking water.

The report, *The Urban Water Blueprint*, analyses the state of water supplies in 534 cities and 2,000 watersheds to provide a comprehensive overview of the potential natural solutions that can be integrated with traditional infrastructure. The results are compelling. Water quality for more than 700 million people could be significantly improved by adopting conservation practices in watersheds. And at least one in four cities examined would find such interventions financially viable, based solely on savings from avoided water-treatment costs.

In some places, such measures have already been introduced. Farmers near Beijing, for example, have been paid to convert crop-lands from rice to corn. Rice paddies need to be constantly flooded, and, because they are often located on steep slopes, this leads to significant runoff of fertilizers and sediment. Shifting to corn not only reduces water consumption; it also cuts the amount of pollution that reaches city residents downstream. The programme costs about $1,330 per hectare of farmland to implement, but produces $2,020 per hectare of benefits.

In Brazil, a water-conservation fund is working to restore the Cantareira watershed, the source of 50% of Sao Paulo's water. The area has lost 70% of its original forest cover, and sediment from eroding hillsides has clogged the city's reservoir, jeopardizing the water supply of Brazil's largest city. Under the new programme, farmers and ranchers are paid $120 per hectare to reforest or terrace their fields. So far, about 3,500 hectares have been planted with trees or put under improved soil-management practices. Reforesting another 14,200 hectares could cut the concentration of sediment in the watershed by half.

The savings produced by these programs should be viewed in the context of the $90 billion per year that cities spend to build treatment plants, pipes, and other components of water infrastructure. The authors of *The Urban Water Blueprint* have calculated that more than $18 billion could be productively directed toward conservation activities, saving cities money and creating a new market comparable in size to the market for the water sector's existing technologies.

But if these solutions are to be adopted at the necessary scale, environmentalists and city officials alike will have to expand the scope of their traditional activities. Environmentalists will have to embrace the idea that conservation does not only mean protecting pristine landscapes. It also sometimes requires the improvement of lands under production. Indeed, these are the areas where some of the most cost-effective solutions are to be found. Water quality would be improved for more than 600 million people if the farms and ranches operating within their watersheds limited runoff and restored stream banks.

City officials, meanwhile, need to think beyond their municipalities' boundaries. The 100 largest cities occupy much less than 1% of the planet's land, but the watersheds on which they depend account for a full 12%. Because many cities share water resources, cross-jurisdictional financing mechanisms and a shared sense of commitment will be needed in order to protect and restore natural sources of clean water. These partnerships will require the cooperation of a broad variety of interest groups, all of which will have to be persuaded to support efforts to improve the water supply. Farmers and ranchers should be at the top of the engagement list.

Land use and water security are firmly linked. By embracing both natural and traditional water infrastructure, cities will not only secure their future water supply; they will also reshape our planet's landscape for the better.

©2014/PROJECT SYNDICATE

Comments are welcome at theirview@livemint.com